भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 334 का उत्तर

पीएम गति शक्ति के अंतर्गत सिरोही जिला मुख्यालय को जोड़ना

334. श्री लुम्बा राम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत सिरोही जिला मुख्यालयों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का विचार है क्योंकि आकांक्षी जिला सिरोही का जिला केन्द्र आज भी रेल नेटवर्क से कटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार सिरोही जिला केन्द्र को मारवाड़ बागरा और पिंडवाड़ा के रास्ते रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना बना रही है क्योंकि ये क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए रेल नेटवर्क से संपर्क की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान सहित देश के उन जिला मुख्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ङ) क्या सरकार ने सभी जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

s.k

पीएम गति शक्ति के अंतर्गत सिरोही जिला मुख्यालय को जोड़ने के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री लुम्बा राम के अतारांकित प्रश्न सं. 334 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति राज्य-वार/जिला-वार/क्षेत्र-वार/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम मील संपर्क, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेल की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के संबंध में थ्रोफॉर्वर्ड, धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता हैं। जिला मुख्यालयों सहित रेलवे नेटवर्क से असंबद्ध क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों को मंजूरी देना भारतीय रेल की निरंतर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान सहित भारतीय रेल में लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपये लागत की 44,488 कि.मी. कुल लंबाई वाली 488 रेल परियोजनाएं (187 नई लाइनें, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) हैं, जो योजना/अनुमोदन/निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 12,045 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 2.92 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। ये परियोजनाएं जिला मुख्यालयों सहित रेल नेटवर्क से असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करेंगी।

s.k

राजस्थान

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 4191 किमी लंबाई के लिए 51814 करोड़ रुपये की लागत वाली 32 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (15 नई लाइनें, 05 आमान परिवर्तन और 12 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 1183 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च 2024 तक 14786 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। इसमे शामिल है:

- **20997 करोड़ रुपये की लागत वाली 1230 किमी की कुल लंबाई हेतु 15 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 134 किमी लंबाई को कमीशन किया गया है और मार्च 2024 तक 3593 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।**

- **8334 करोड़ रुपये की लागत वाली 1252 किलोमीटर की कुल लंबाई की 05 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 759 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया गया है और मार्च 2024 तक 5398 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।**

- **22483 करोड़ रुपये की लागत वाली 1709 किलोमीटर की कुल लंबाई की 12 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 290 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया गया है और मार्च 2024 तक 5794 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।**

वर्ष 2014 से, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि और तदनुसार कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन निम्नानुसार किया गया है:-

s.k

अवधि	औसत परिव्यय	वर्ष 2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में परिवर्तन
2009-14	682 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2023-24	9532 करोड़ रु.	लगभग 14 गुना

पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 और मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान राजस्थान राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुल 4,894 किलोमीटर लंबाई की कुल 54 परियोजनाओं (23 नई लाइन और 31 दोहरीकरण) के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है। इन सर्वेक्षणों में जिला मुख्यालयों सहित रेल नेटवर्क से असंबद्ध क्षेत्रों से संपर्क शामिल है।

सिरोही-मारवाड़ बागरा-पिंडवाड़ा नई लाइन (96 किमी) के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है परन्तु कम यातायात अनुमानों के कारण परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। बहरहाल, पिंडवाड़ा और मारवाड़ बागरा मौजूदा रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

वर्ष 2023-24 में गतिशीलता में सुधार और बढ़ती यातायात संबंधी मांग को पूरा करने के लिए, लूनी-समदड़ी-भिलड़ी (271.97 किलोमीटर) खंड के बीच 3085.59 करोड़ रुपये की लागत से दोहरीकरण के कार्य को मंजूरी दी गई है।

दोहरी लाइन वाला समर्पित माल यातायात गलियारा (डीएफसी) भी राजस्थान के सिरोही जिले से गुजरता है।

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर स्टेशनों को विकसित करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की गई है।

s.k

इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसमें स्टेशनों पर स्टेशन पहुंच मार्ग में सुधार, परिपथन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्धारित स्थान, भूदृश्यता में सुधार आदि जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध रूप में उनका कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के अनुसार भवन में सुधार, शहर के दोनों ओर स्टेशन को एकीकृत करने, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थाई और पर्यावरण अनुकूल साधन, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान, और दीर्घ अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

अभी तक इस योजना के अंतर्गत विकास करने हेतु राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ने वाले आबू रोड और पिंडवाड़ा स्टेशनों सहित 1324 स्टेशनों की पहचान की गई है।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

*****

s.k